साप्ताहिक
निष्पक्ष...निर्भीक...निरंतर...
विश्वास का तीर
सपांदक- आयुष राजपूत
RNI.NO- MPHIN/2022/83636
वर्ष-03 | अंक-37 | भोपाल, प्रति शुक्रवार 23 अगस्त 2024 | मूल्य-10 रूपयें | पृष्ठ-08

खुद शिकायत कराता था सीबीआई का डीएसपी

विश्वास का तीर

सिंगरौली के नॉर्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में कथित भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामले में सीबीआई ने अपने ही डीएसपी जॉय जोसेफ दामले को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक डीएसपी ने एनसीएल के ठेकेदारों और अफसरों के साथ मिलकर घूसखोरी का पूरा नेटवर्क खड़ा किया था। पहले वह खुद एनसीएल में हो रहे घोटालों की शिकायतें करवाता फिर जांच के नाम पर घूस लेकर क्लीन चिट देता था। घूस की रकम हासिल करने के लिए उसका सबसे खास गुर्गा ठेकेदार रविशंकर था। बिहार का रहने वाला रविशंकर पहले बस कंडक्टर था फिर वो एनसीएल का ठेकेदार बन गया। सिंगरौली में ही उसने 5 करोड़ का बंगला बनाया है। उसके खिलाफ पांच साल पहले इनकम टैक्स की कार्रवाई भी हो चुकी है। जिसमें 65 अधिकारियों के नाम की लिस्ट मिली थी। ये दूसरा मौका है जब सीबीआई ने अपने ही अधिकारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इससे पहले नर्सिंग घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों ने भी नर्सिंग कॉलेजों को क्लीन चिट देने के एवज में रिश्वत लेने का पूरा नेटवर्क तैयार किया था। इसमें दलाल, कॉलेज संचालक और पटवारी शामिल थे।

पहले जानिए कैसे काम कर रहा था घूसखोरी का नेटवर्क

एनसीएल में सिक्योरिटी ऑफिसर रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल बीके सिंह के खिलाफ पिछले दिनों एक शिकायत हुई थी। शिकायत थी कि बीके सिंह ठेकेदारों से मिलकर सिक्योरिटी गार्ड की संख्या में गड़बड़ी कर विभाग को चपत लगा रहे हैं। ये शिकायत एनसीएल के विजिलेंस डिपार्टमेंट और सीबीआई को की गई थी। जांच का जिम्मा डीएसपी जॉय जोसेफ दामले का था। हकीकत में डीएसपी जोसेफ ने ही ये शिकायत करवाई थी, ताकि वह बीके सिंह से रिश्वत की रकम वसूल सके। इसका खुलासा तब हुआ जब डीएसपी ने सीएमडी के स्टेनो सूबेदार ओझा के जरिए बी के सिंह तक शिकायत की खबर भिजवाई। बीके सिंह ने सूबेदार ओझा से पूछा कि इस शिकायत का निपटारा कैसे होगा?

इसके बाद डीएसपी के घूसखोरी का नेटवर्क सक्रिय हुआ। स्टेनो ओझा ने बीके सिंह को मेसर्स संगम इंजीनियर के डायरेक्टर और ठेकेदार रविशंकर सिंह से मिलने के लिए कहा। रविशंकर रिश्वत की रकम डीएसपी के पास पहुंचाता था। रविशंकर ने बीके सिंह से कहा कि डीएसपी उनके पक्ष में रिपोर्ट देंगे इसके लिए कीमत चुकाना पड़ेगी। उनके बीच एक तय रकम पर सौदा हुआ। पहली पेशगी के तौर पर तय हुआ कि बीके सिंह 5 लाख रुपए और एक आईफोन रविशंकर सिंह के माध्यम से डीएसपी दामले को भिजवाएंगे।

2 अगस्त को रविशंकर ने डीएसपी दामले तक आईफोन भिजवाया

सीबीआई की एफआईआर में जिक्र है कि रविशंकर ने बीके सिंह से दिल्ली से आईफोन खरीदवाया। इसके बाद पंकज ट्रैवल की बस के जरिए इसे जबलपुर तक भिजवाया। बस ट्रैवल के कर्मचारी सुकचेन सिंह ने इसे पुलिस विभाग में पदस्थ स्टेनो कमल सिंह को सौंपा था। कमल ने 2 अगस्त को इसकी डिलीवरी डीएसपी दामले को की। 6 अगस्त को कमल सिंह ने जबलपुर से एक सिम भी खरीदकर दामले को दी थी। कमल सिंह लंबे अर्से से महिला आईजी कार्यालय में रहा है। अब भी वह जबलपुर में ही पदस्थ है और रविशंकर का मौसेरा भाई है। कहा जाता है कि रविशंकर सिंह अपने इस मौसेरे भाई के जरिए जबलपुर इनकम टैक्स की विजिलेंस टीम के अलावा सीबीआई अधिकारियों से संपर्क साधता था।

5 लाख रु. की डिलीवरी लेते वक्त डीएसपी पकड़ा गया

आईफोन पहुंचाने के बाद बारी 5 लाख रु. देने की थी। रविशंकर ने कमल को ही कहा कि वह 5 लाख रु. डीएसपी दामले तक पहुंचा दे। कमल ने किसी कारण से ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद रविशंकर ने रिश्वत की रकम पहुंचाने का जिम्मा अपने दूसरे साथी दिवेश सिंह को सौंपा। दिवेश को 16 अगस्त को ये रकम डीएसपी दामले तक पहुंचाना थी। दिल्ली की सीबीआई टीम इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही रिश्वत की रकम के लेन देन की तारीख तय हुई। सीबीआई ने 15 अगस्त की रात एफआईआर दर्ज की। इसमें लिखा कि दिवेश सिंह डीएसपी दामले को 16 अगस्त को रिश्वत की रकम सौंपेगा। इधर दिवेश रिश्वत की रकम लेकर सिंगरौली से जबलपुर के लिए रवाना हुआ उधर दिल्ली से सीबीआई की टीम जबलपुर के लिए रवाना हुई। दोनों 16 अगस्त की सुबह जबलपुर पहुंचे।

डीएसपी के पकड़े जाने के बाद स्टेनो ओझा के घर से 4 करोड़ बरामद किए

दामले और दिवेश की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सीबीआई टीम ने अगले दिन एनसीएल में दबिश दी। टीम ने यहां से रविशंकर सिंह, बीके सिंह और सूबेदार ओझा को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने इनके घर, ऑफिस से ठेके और सप्लाई से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। वहीं स्टेनो सूबेदार ओझा के घर में छापे के दौरान 3.85 करोड़ रुपए जब्त किए। यहां से भी कई अहम दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे हैं। सीबीआई ने सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए 24 अगस्त तक रिमांड पर लिया है। अभी कमल सिंह को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन उसे एफआईआर में आरोपी बनाया गया है। स्टेनो ओझा के घर से जो रकम बरामद की गई उसके बारे में पता चला है कि ये ठेकेदारों से वसूल की गई रकम है। इसके बाद ओझा इस रकम का बंटवारा करने वाला था। इसमें सीबीआई के अलावा दूसरे विभाग के अधिकारी, एनसीएल के कुछ बड़े अधिकारी और कुछ सफेदपोशों का हिस्सा था।

अब जानिए रविशंकर के बारे में, 20 साल में बना करोड़पति

एनसीएल का ठेकेदार रविशंकर मूलत बिहार का रहने वाला है। वह पिछले 20 साल से एनसीएल में सक्रिय है, लेकिन उसका असली खेल 2010 में शुरू हुआ। एनसीएल में बिहार के सबसे ज्यादा मजदूर, अधिकारी और कर्मचारी है। रविशंकर ने इनके जरिए अपनी लॉबी तैयार की। 11 साल पहले एनसीएल के मुख्य महाप्रबंधक रहे मुरलीराम के समय उसने पैठ बढ़ाना शुरू की और ठेके लेने लगा। जब एनसीएल के सीएमडी भोला सिंह बने, तो रविशंकर सिंह का दखल और बढ़ गया। दरअसल, भोला सिंह पूर्व में एनसीएल में ही माइनिंग अफसर थे। बाद में वे रिलायंस पावर के मुख्य हेड बन गए थे। भोला सिंह बैढ़न में रविशंकर सिंह के पड़ोस में ही रहते थे। इस दौरान उनकी नजदीकी और बढ़ गई। जब भोला सिंह एनसीएल के सीएमडी बने, तो रविशंकर सिंह ही एक तरह से उनके पावर का प्रयोग करने लगा था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एनसीएल की ओर से उसे जयंत सेक्टर में खुद का कार्यालय बनाने के लिए जगह तक दी गई थी। यहां तक कि एनसीएल के गोपनीय इंटरकाम का कनेक्शन भी उसे दिया गया था। एनसीएल में कोई भी ठेका हो, वह रविशंकर सिंह को या फिर उसके चहेते को मिलता था। ठेका किसी कारण दूसरे को मिल भी जाए, तो उसका काम भी रविशंकर ही कराता था।

छतरपुर थाने पर पथराव के आरोपी की कोठी तोड़ी

संभागायुक्त ने कहा- बिना परमिशन बनी थी; सांसद प्रतापगढ़ी बोले- ये संविधान कुचलने जैसा

विश्वास का तीर

छतरपुर में सिटी कोतवाली पर बुधवार को हुए पथराव मामले में सीएम डॉ मोहन यादव के निर्देश के बाद पुलिस एक्शन मोड पर है। गुरुवार को पुलिस ने पथराव के मुख्य आरोपी पूर्व कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलवाया। संभाग कमिश्नर ने कहा कि, कोठी 20 हजार वर्ग फीट में बगैर परमिशन के बनाई गई है। इस दौरान अंदर खड़ी फॉर्च्यूनर समेत तीन कारों को जेसीबी की मदद से दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। कारों पर भी जेसीबी चढ़ा दी गई। मुख्य आरोपी शहजाद अली परिवार समेत फरार हो गया है। उधर, पुलिस ने करीब 20 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कोतवाली से कोर्ट तक उनका जुलूस निकाला गया। इस मामले को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने ङ्क अकाउंट पर लिखा- भाजपा सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और उदाहरण देखिए। उनकी राज्य सरकारें बहाना तलाश कर मुसलमानों का घर तोड़ रही हैं, संविधान की शपथ लेने वाली मोदी सरकार इस बुलडोजर के नीचे हर दिन संविधान को कुचल रही है। जल्द ही इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा। उन्होंने बिना नोटिस दिए घर और गाड़ियां तोड़ने वाले अफसरों पर कार्रवाई करने की मांग की। इधर, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि उन्होंने जिस तरह का आतंक मचाने का काम किया। ऐसे गुंडे, ऐसे अपराधी छतरपुर में एक कदम भर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद कर देंगे। किसी को नहीं छोड़ेंगे।

पथराव के दौरान भीड़ में सबसे आगे था शहजाद

जानकारी के मुताबिक जिला कांग्रेस कमेटी का पूर्व उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली बुधवार को भीड़ में वह ज्ञापन सौंपने वालों में सबसे आगे था। पथराव की घटना के बाद से ही पुलिस उस पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में थी। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। रात भर पुलिस फोर्स मार्च पास्ट करती रही। गुरुवार सुबह टीकमगढ़, पन्ना समेत सीमा से लगे जिलों से भी अतिरिक्त फोर्स को बुला लिया गया। सुबह से पूरे मामले को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की गई। अचानक सुबह करीब 10 बजे पुलिस लाइन में फोर्स जमा होने लगी। कुछ देर बाद सभी सीनियर अधिकारी भी पुलिस लाइन पहुंच गए।

ऐसे शुरू हुआ एक्शनः बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस फोर्स

सभी थानों के टीआई, पुलिसकर्मी, राजस्व अमला, नगर पालिका और मेडिकल टीमें आरोपी हाजी शहजाद अली की कोठी पहुंचीं। कड़ी सुरक्षा के बीच टीम ने करीब 11.30 बजे कार्रवाई शुरू की। टीम को देखते ही यहां मौजूद कुछ लोग भाग खड़े हुए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया। कोठी के कुछ हिस्से का निर्माण चल रहा था। वहीं, अंदर तीन लग्जरी कारें खड़ी मिलीं। पुलिस ने जेसीबी की मदद से ताला तोड़कर कोठी को ढहाना शुरू कर दिया।

चार मशीनों ने 8 घंटे में हवेली को नेस्तनाबूद कर दिया

मस्तान शाह कॉलोनी में हाजी शहजाद अली ने नई कोठी बनाई थी। अपने चार भाइयों के साथ वो हवेली में शिफ्ट होने वाला था। फिलहाल यहां कोई नहीं रहता था। दो मंजिला कोठी 20 हजार वर्ग में बनाई गई थी। गुरुवार सुबह सबसे पहले जेसीबी की मदद से हवेली के भीतर बड़ी मशीनों को ले जाने का रास्ता बनाया गया। 8 घंटे तक चली कार्रवाई में आलीशान कोठी खाक में मिल गई। हवेली के भीतर तीन लग्जरी कारें, एक बाइक भी थी, जिसे मशीनों के जरिए बाहर निकाला गया। इस दौरान उनकी हालत कबाड़ जैसी हो गई। कोठी में बेड रूम के भीतर दो राइफल भी बरामद की गई हैं।

20 हजार वर्ग फीट में बनी थी आलीशान कोठी

नायब तहसीलदार इंदु गौड़ ने बताया कि आरोपी हाजी शहजाद अली ने मकान बनाने की परमिशन नहीं ली थी। इसलिए उसके बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। आरआई देवेंद्र पटेरिया ने बताया कि हाजी की कोठी 20 हजार वर्ग फीट में बनी थी। जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ है।

एसपी ने कहा- अवैध संपत्तियों की जांच कराई जाएगी

एसपी अगम जैन ने भी कहा कि, अपराधियों को चिन्हित कर उनकी अवैध संपत्तियों की जांच कराई जाएगी। इन पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) और जिला बदर जैसी कार्रवाई भी करेंगे। जिन लोगों के पास शस्त्रों के लाइसेंस हैं उन्हें भी निरस्त कराया जाएगा।

30 से ज्यादा हिरासत में लिए गए, आरोपियों का जुलूस निकाला

पुलिस ने पथराव करने वाले 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। गुरुवार शाम को पथराव करने वाले करीब 20 आरोपियों को हिरासत में लेकर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस इन आरोपियों को कोतवाली से कोर्ट तक पैदल लेकर पहुंची। आरोपी नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कह रहे थे पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है।

घटना के विरोध में व्यापारियों ने बंद किया बाजार

पुलिस पर हुए पथराव के बाद चौक बाजार इलाके में बुधवार शाम से ही दहशत है। व्यापारियों ने गुरुवार को सांकेतिक रूप से अपनी दुकानें बंद कर घटना का विरोध किया। वहीं, कोतवाली पहुंचकर पुलिस का हौसला बढ़ाया। उन्होंने एसपी को एक ज्ञापन देते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

शिकायत लेकर पहुंचे थे, हाथ में हथियार भी थे

दरअसल, बुधवार (21 अगस्त) शाम करीब 5 बजे थाने में शिकायती आवदेन लेकर पहुंचे थे। धीरे-धीरे और लोग जमा होते गए। सभी थाने के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान भीड़ में कुछ लोग पुलिस को हथियार और हाथ में पत्थर लिए नजर आए। पुलिस ने मेन गेट बंद कर दिया।

भीड़ ने पथराव शुरू किया, पुलिसकर्मी थाने के भीतर भागे

मेन गेट के बंद होते ही भीड़ ने और जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ पुलिसकर्मी उन्हें शांत करवाने बाउंड्री वाल पर चढ़े। वे उन्हें शांत रहने की बात कहते रहे। टीआई अरविंद कुंजर भी आवेदन लेने थाने बाहर निकले। वे मेन गेट पर पहुंचे ही थे कि भीड़ में आए लोग विवाद करने लगे। बाहर से पथराव शुरू हो गया। बांउड्रीवॉल पर खड़े जवान कूदकर थाने के अंदर भागे।

भोपाल में पुलिस से बोले आरोपी- हमें तो खाते देने के एवज में कमीशन मिलता था

शेयर मार्केट में इंवेस्टमेंट के नाम से ठगने वाले गिरफ्तार

विश्वास का तीर

भोपाल के कोहेफिजा में रहने वाले कारोबारी से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 9.35 लाख की ठगी करने वाले तीन आरोपियों को साइबर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों भुसावल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों बताया कि उन्होंने केवल अपने खाते इस्तेमाल को दिए थे। इसके एवज में उन्हें महज 20-20 हजार रुपए मिले थे। ठगी किसने की, रकम आगे कहां गई इसकी जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जैनुल निवासी कोहेफिजा ने दो महीने पहले थाना साइबर क्राइम भोपाल में लिखित शिकायत की थी। इसमें बताया कि उनके वॉट्सऐप पर करण बिरला नाम के व्यक्ति ने कॉल किया था। उसने स्वयं को शेयर ब्रोकर बताया था। ट्रेडिंग के लिए PMHDFC नाम के एप्लिकेशन डाउन लोड कराई। इसके बाद इस एप्लिकेशन से सहराज सोलार नाम की कंपनी में इन्वेस्ट करने पर बड़ा मुनाफा कमाने का लालच दिया। आरोपी की बातों में आने के बाद फरियादी ने तीन बार में उसके बताए खाते में 9.35 लाख रुपए जमा कर दिए। बाद में ऐप लॉक कर दिया गया, आरोपी का वॉट्सऐप नंबर भी बंद हो गया।

नामी कंपनियों से मिलता-जुलता

एप्लिकेशन तैयार किया जाता है

साइबर जालसाज लोगों को वॉट्सऐप पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर मैसेज भेजते हैं। लोगों को शेयर मार्केट में बड़ी कंपनियों के नाम से इन्वेस्ट करने पर कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का लालच देते हैं। नामी कंपनियों से मिलता-जुलता एप्लिकेशन बनाया जाता है। लोग जब पहली बार कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तब उनको मुनाफा सहित जमा की गई राशि वापस कर दी जाती है। इसके बाद बड़ी राशि इन्वेस्ट की जाती है, तब उनको कोई पैसा वापस नहीं किया जाता है।

ऐसे आरोपियों तक पहुंची पुलिस

साइबर क्राइम ने मैदानी स्तर पर प्राप्त साक्ष्य एवं तकनीकी एनालिसिस के आधार पर प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अपराध कारित करने में उपयोग किए गए वॉट्सऐप नंबर, एप्लिकेशन एवं बैंक खातों के वास्तविक उपयोग कर्ता की तकनीकी जानकारी प्राप्त की गई। इसके बाद मैदानी स्तर पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रयास कर वास्तविक आरोपियों को बैंक खाता बेचने वाले आरोपियों की पहचान की गई। तकनीकी एवं मैदानी स्तर पर प्राप्त जानकारी के आधार पर गिरोह को पैसे लेकर खाता बेचने वाले तीन आरोपियों को भुसावल महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त 3 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड जब्त किए हैं। अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।

जानिए कौन हैं गिरफ्तार साइबर जालसाज

- अनिकेत दत्तात्रेय बरहटे निवासी भुसावल जिला जलगांव महाराष्ट्र आईटीआई डिप्लोमा होल्डर है। उसने स्वयं के नाम पर फर्जी खाते खुलवाकर पैसे लेकर इन खातों को साइबर जालसाजों को दिया था।
- ऋषिकेश प्रवीण बाविस्कर निवासी भुसावल जिला जलगांव महाराष्ट्र आईटीआई डिप्लोमा होल्डर है। फर्जी खाते खरीदकर आरोपी आकाश चनाड़े को पैसे लेकर बेचता था।
- आकाश चनाड़े निवासी भुसावल जिला जलगांव महाराष्ट्र भी आईटीआई डिपलोमा होल्डर है। आरोपी फर्जी खाते खरीदकर अन्य आरोपियों को पैसे लेकर बेचता था। इसके एवज में उसे कमीशन मिलता था।

साइबर ठगी होने पर तत्काल इन नंबरों पर दें सूचना

साइबर क्राइम संबंधित घटना की सूचना भोपाल साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 9479990636 अथवा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दे सकते हैं। समय पर सूचना मिलने पर पुलिस आपके खाते से जिन खाते में रकम ट्रांसफर कराई गई उसे सीज करा सकती है।

आईपीएस सुशील रंजन, रामशरण जाएंगे मणिपुर

विश्वास का तीर

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मणिपुर में पदस्थ एमपी के दो आईपीएस अधिकारियों के स्थान पर दो नए आईपीएस अफसरों को मणिपुर राज्य के लिए पदस्थ कर दिया है। पूर्व में जिन आईपीएस अधिकारियों को मणिपुर भेजने का फैसला लिया गया था, वे वापस लौटना चाहते हैं, इसलिए अब उनके स्थान पर दूसरे आईपीएस अफसरों को भेजने के आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत सरकार ने 7 अगस्त 2023 को एमपी कैडर के पुलिस अधीक्षक स्तर के तीन अधिकारियों को मणिपुर में पदस्थ करने का निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने दो आईपीएस अधिकारियों आलोक कुमार सिंह और राजीव कुमार मिश्रा को मणिपुर राज्य में पदस्थापना के लिए रिलीव किया था। दोनों ही अधिकारी अभी मणिपुर में सेवाएं दे रहे हैं। बताया जाता है कि दोनों ही अफसरों ने मणिपुर से अपने मूल कैडर एमपी में वापसी को लेकर आवेदन किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने दोनों ही आईपीएस अफसरों को मूल कैडर में वापसी पर सहमति दे दी है। इनके स्थान पर अब 2011 बैच के आईपीएस सुशील रंजन

सिंह सेनानी 9वीं वाहिनी विसबल रीवा और 2016 बैच के आईपीएस रामशरण प्रजापति सहायक पुलिस महानिरीक्षक एससीआरबी पुलिस मुख्यालय भोपाल को मणिपुर राज्य के लिए पदस्थापना के लिए अधिकृत किया गया है। सीबीआई को भी इन अफसरों की पदस्थापना की जानकारी दी गई है।

दोनों मणिपुर ज्वाइन करेंगे तभी वहां पदस्थ अफसर होंगे रिलीव

गृह विभाग द्वारा सुशील रंजन सिंह और रामशरण प्रजापति की मणिपुर राज्य में कर्तव्य के लिए पदस्थापना के लिए अधिकृत किए जाने के साथ पुलिस महानिदेशक को यह निर्देश भी दिए हैं कि जब तक सुशील रंजन और रामशरण मणिपुर राज्य में अपनी उपस्थिति नहीं देते हैं तब तक आलोक कुमार सिंह और राजीव कुमार मिश्रा मणिपुर से रिलीव नहीं होंगे। डीजीपी को मणिपुर के लिए पदस्थ किए गए दोनों ही आईपीएस अफसरों को जल्द रिलीव करने के निर्देश भी गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में दिए गए हैं।

सीबीआई की स्ट्रक्चर में शामिल हुए थे MP के 3 IPS

मणिपुर हिंसा की जांच के लिए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया। इसके लिए मध्य प्रदेश के तीन आईपीएस अधिकारियों को सीबीआई में नियुक्त किया गया। इन अधिकारियों में भिंड में 17वीं बटालियन में तैनात 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी आशुतोष बागरी के अलावा शिवपुरी में 18वीं बटालियन से आलोक कुमार सिंह और अतिरिक्त आईजी और पुलिस मुख्यालय में महिला सुरक्षा प्रभारी के रूप में तैनात राजीव मिश्रा को मणिपुर पदस्थ किया गया था।

आलेख

भारतीय बच्चों में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्ति चिन्ताजनक

भारतीय बच्चों में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्ति चिन्ताजनक है। पिछले कुछ समय से स्कूली बच्चों में बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति निश्चित रूप से डरावनी एवं खौफनाक है। चिंता का बड़ा कारण इसलिए भी है क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास की नींव रखी जाती है, उसी उम्र में कई बच्चों में आक्रामकता घर करने लगी है और उनका व्यवहार हिंसक होता जा रहा है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई-लिखाई और खेलकूद में व्यस्त रहना चाहिए, उसमें उनमें बढ़ती आक्रामकता, हिंसा एवं क्रूरता एक अस्वाभाविक और परेशान करने वाली बात है। कई घटनाओं में स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे ने अपने सहपाठी पर चाकू या किसी घातक हथियार से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। अमेरिका की तर्ज पर भारत के बच्चों में हिंसक मानसिकता का पनपना हमारी शिक्षा, पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना पर कई सवाल खड़े करती है। यह दुष्प्रवृत्ति बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर तो नकारात्मक प्रभाव डाल ही रही है, इसे भविष्य में समाज की शांति के लिए बड़ा खतरा भी मानना चाहिए। राजस्थान के उदयपुर के स्कूल में दो छात्रों के आपसी विवाद में चाकू मारने से एक छात्र की मौत भी बच्चों में पनप रहे इसी हिंसक बर्ताव का घिनौना एवं घातक रूप है। बड़ा सवाल है कि जिन वजहों से बच्चों के भीतर आक्रामकता एवं हिंसा पैदा हो रही है, उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है! पाठ्यक्रमों का स्वरूप, पढ़ाई-लिखाई के तौर-तरीके, बच्चों के साथ घर से लेकर स्कूलों में हो रहा व्यवहार, उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों का दायरा, संगति, सोशल मीडिया या टीवी से लेकर उसकी सोच-समझ को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों से तैयार होने वाली उनकी मन:स्थितियों के बारे में सरकार, समाजकर्मी एवं अभिभावक क्या समाधान खोज रहे हैं। बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा? बच्चों के बस्ते की औचक जांच की व्यवस्था की अपनी अहमियत हो सकती है। मगर जरूरत इस बात की है कि बच्चों के भीतर बढ़ती हिंसा और आक्रामकता के कारणों को दूर करने को लेकर गंभीर काम किया जाए। उदयपुर की घटना के पूरे मामले की पुलिस अपने तरीके से जांच करेगी, लेकिन किशोर अवस्था में ऐसी घटना को अंजाम देने के पीछे बच्चे की मानसिकता का पता लगाना भी ज्यादा जरूरी है। तहकीकात स्कूल की व्यवस्थाओं की भी होनी चाहिए कि आखिर बच्चा स्कूल में हथियार लेकर कैसे आ गया? इसमें दो राय नहीं कि किशोरवय में राह भटकने का खतरा ज्यादा रहता है। उम्र के इस पड़ाव पर उनको सही राह दिखाने की जिम्मेदारी परिजन और शिक्षक की ही होती है। आज दोनों ही कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी से दूर होते नजर आ रहे हैं। स्कूल में केवल किताबी ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहीं अर्थप्रधान दुनिया में माता-पिता के पास बच्चों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं बच पा रहा। 'मन जो चाहे वही करो' की मानसिकता वहां पनपती है जहां इंसानी रिश्तों के मूल्य समाप्त हो चुके होते हैं, जहां व्यक्तिवादी व्यवस्था में बच्चे बड़े होते-होते स्वछन्द हो जाते हैं। 'मूड ठीक नहीं' की स्थिति में घटना सिर्फ घटना होती है, वह न सुख देती है और न दु:ख। ऐसी स्थिति में बच्चे अपनी अनंत शक्तियों को बौना बना देता है। यह दकियानूसी ढंग है भीतर की अस्तव्यस्तता को प्रकट करने का। पारिवारिक एवं सामाजिक उदासीनता एवं संवादहीनता से ऐसे बच्चों के पास सही जीने का शिष्ट एवं अहिंसक सलीका नहीं होता। वक्त की पहचान नहीं होती। ऐसे बच्चों में मान-मर्यादा, शिष्टाचार, संबंधों की आत्मीयता, शांतिपूर्ण सहजीवन आदि का कोई खास ख्याल नहीं रहता। भौतिक सुख-सुविधाएं ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाता

है। भारतीय बच्चों में इस तरह का एकाकीपन उनमें गहरी हताशा, तीव्र आक्रोश और विषैले प्रतिशोध का भाव भर रहा है। वे मानसिक तौर पर बीमार बन रहे हैं और अपने पास उपलब्ध खतरनाक एवं घातक हथियारों का इस्तेमाल कर हत्याकांड कर बैठते हैं। शिक्षकों और परिजनों से संवादहीनता के चलते बच्चों ने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया को संवाद का जरिया बना लिया है। कई बार टी.वी. पर हिंसक कार्यक्रम देखने आदि से बच्चों में हिंसक व्यवहार बढ़ जाता है। घर में लगातार बंदूकें, चाकू आदि देखते रहने से भी बच्चों का व्यवहार हिंसक हो जाता है। वैसे भी अगर बच्चों को किसी भी बात के लिए मना नहीं करेंगें, टोकेंगें नहीं तो उन्हें अच्छे-बुरे की पहचान कैसे होगी। एक ऑनलाइन सर्वे में माता-पिता ने कहा था कि बच्चों को गलत काम की सजा भी मिलनी चाहिए, वरना उनके मन में किसी भी बात के लिए डर नहीं रहेगा और हो सकता है वे ऐसे अपराधों को भी अंजाम देने लगें, जिनके परिणामों के बारे में उन्हें पता नहीं। स्कूली बच्चों में पिछले कुछ समय से हिंसक प्रवृति तेजी से बढ़ रही है, जो समाज के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। मनोविज्ञानी यह मानते हैं कि मोबाइल पर पबजी जैसे खतरनाक गेम और वेब सीरीज बच्चों को हिंसक बना रही है। लेकिन, इसके पीछे न सिर्फ स्कूल का वातावरण, बल्कि लाड-प्यार में अंधे अभिभावकों का रवैया भी कम जिम्मेदार नहीं है। बच्चों में हिंसक व्यवहार के संकेत, जैसे गलत भाषा का प्रयोग करना, समझाने पर भी गुस्सा करना, कोई भी बात समझाने पर चीजें फेंकने लगना, मां-बाप को ही मारने दौडना, लोगों के बारे में गलत बोलना, गलत आदतों में पडना, भाई-बहन के लिए स्नेह न रखना, लड़ाकू प्रवृति का होना, हमेशा उदास रहना, संवेदनहीन और चिड़चिड़े रहना, बार-बार जोश में आना आपको नजर आ सकते हैं। एकल परिवारों में माता-पिता इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास बच्चों से बात करने का ज्यादा समय नहीं होता।

आखिर कैसी देश की आजादी के पक्षधर हैं हम?

संपादकीय

15 अगस्त का दिन प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव का दिन है क्योंकि इसी दिन भारत को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति मिली थी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश के प्रत्येक नागरिक के दिलोदिमाग में एक अलग ही जज्बा और उत्साह समाहित रहता है। हालांकि वर्षों की गुलामी के बाद गुलामी की इन जंजीरों से मिली आजादी को हम किस रूप में संजोकर रख पा रहे हैं, वह सभी के समक्ष है। देश को आजाद हुए पूरे 77 बरस हो चुके हैं लेकिन आजादी के इन 77 वर्षों में लोकतंत्र के पवित्र स्थल संसद और विधानसभाओं के हालात साल दर साल किस कदर बदले हैं, वह भी किसी से छिपा नहीं है, जहां अभद्रता की सीमा पार करते जनप्रतिनिधि अभद्रता की हर हद पार करते नजर आते हैं। प्रतिवर्ष जब देश की स्वतंत्रता के साथ-साथ राष्ट्र की आन-बान और शान के प्रतीक तिरंगे के नीचे खड़े होकर बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी देश की रक्षा व प्रगति का संकल्प लेते देखते हैं, जो वर्षभर सरेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते देखे जाते हैं तो मन में यही सवाल उठता है कि आखिर ऐसी संकल्प अदायगी से देश को हासिल क्या होता है? आजादी के दीवानों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस देश को आजाद कराने के लिए वे इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं, आजादी की उसकी तस्वीर ऐसी हो जाएगी। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश ने विकास के मार्ग पर तेजी से कदम बढ़ाए और विकास के अनेक सोपान तय किए हैं। तकनीकी कौशल हासिल करते हुए देश अंतरिक्ष तक जा पहुंचा है लेकिन महिलाओं से दुर्व्यवहार की घटनाएं जिस प्रकार लगातार बढ़ रही हैं और समाज में अपराधों की तादाद भी बढ़ रही है, ऐसे में देश की गुलामी का दौर देख चुके कुछ बुजुर्ग तो अब कहते सुने भी जाते हैं कि गुलामी के दिन आज की इस आजादी से कहीं बेहतर थे, जहां अपराधों को लेकर मन में भय व्याप्त रहता था किन्तु कड़े कानून बना दिए जाने के बावजूद अपराधियों के मन में अब किसी तरह का भय नहीं दिखता। देश के कोने-कोने से सामने आते अबोध बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के बढ़ते मामले आजादी की बेहद शर्मनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं। देश में महंगाई सुरसा की तरह बढ़ रही है, मध्यम वर्ग के लिए जीवनयापन दिनों-दिन मुश्किल होता जा रहा है, आतंकवाद की घटनाएं पग पसार रही हैं, आरक्षण की आग रह-रहकर देश को जलाती रहती है। ऐसे हालात निश्चित तौर पर देश के विकास के मार्ग में बाधक बनते हैं। हर कोई सत्ता के इर्द-गिर्द ही अपनी-अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकता नजर आ रहा है। कहीं कोई सत्ता बचाने में लगा है तो कहीं कोई इसे गिराने के प्रयासों में। संसद और विधानसभाओं में हंगामेदार तस्वीरें तो अब कोई नई बात नहीं रह गई है।

कांग्रेस के दो विधायक वाटर कैनन के प्रेशर से गिरे

भोपाल में बैरिकेड पर चढ़े थे; हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन

विश्वास का तीर

अडाणी-हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी जांच और सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस आज देशभर में प्रदर्शन किया। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बैरिकेड पर चढ़ने का प्रयास कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। इस दौरान पानी के प्रेशर से दो विधायक नीचे गिर गए। अरेरा हिल्स स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर रोक लिया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और महेश परमार ने बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग कर रोका। वहीं श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल को पुलिस ने बेरीकेड से हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता मंजीरे बजाते हुए कार्यालय से निकले और व्यापमं चौराहे पर पहुंचे। यहां सभा हुई। सभा को प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया।

कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन को लेकर ये कहा

भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश प्रभारी, एमपी कांग्रेस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडाणी का नाम लिया जा रहा है। इस चेहरे के नकाब के पीछे मोदी की सरकार छिपी हुई है। मप्र में जल जीवन मिशन में पानी का बड़ा घोटाला हुआ है। जिसमें ये बातें की जा रही थीं कि हम हर गरीब को पानी पिलाएंगे। उस पानी पर इन लोगों ने कमीशन खाया है।

जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष: एक PM ने नारा दिया था ना खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन हालात क्या बने 20 प्रतिशत लोगों के पास देश की 80 प्रतिशत संपत्ति चली गई। 10 साल में गरीबों की डबल संख्या हो गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दो बार सार्वजनिक हुई। एक बार 20 हजार करोड़ रुपए सेल कंपनियों के माध्यम से अडाणी के शेयर मार्केट में हेरा फेरी हुई। रिपोर्ट आने के बाद शेयर धड़ाम से नीचे गिर गया। अजय सिंह राहुल भैया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष- ये वही अडाणी जी हैं जिनके प्रदेश में आजकल घर-घर बिजली के मीटर लग रहे हैं। हमारे विंध्य अंचल में ये हालत है कि कोयला खदान उनकी, पावर प्रोजेक्ट उनका है। आदिवासी भाइयों की जमीन भले डूब जाए लेकिन अडाणी जी का काम चलता रहे। उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री विशेष रुचि लेते हैं।

राहुल बोले- घोटाले की जांच करने वाले ही घोटाले में शामिल

राहुल गांधी ने 11 अगस्त को कहा था कि अडाणी महाघोटाले की जांच SEBI को दी गई। अब खबर है कि SEBI की चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल हैं। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है।

हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट की बड़ी बातें

■अडाणी ग्रुप पर हमारी रिपोर्ट के लगभग 18 महीने हो चुके हैं। रिपोर्ट में इस बात के पुख्ता सबूत पेश किए गए थे कि अडाणी ग्रुप कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा था।

■हमारी रिपोर्ट ने ऑफशोर, मुख्य रूप से मॉरीशस बेस्ड शेल एंटिटीज के एक जाल को उजागर किया था। जिनका इस्तेमाल संदिग्ध अरबों डॉलर के अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए किया गया था।

■सभी सबूतों के अलावा 40 से ज्यादा इंडिपेंडेंट मीडिया इन्वेस्टिगेशन ने हमारी रिपोर्ट की पुष्टि थी। इसके बावजूद सेबी ने अडाणी ग्रुप के खिलाफ कोई पब्लिक एक्शन नहीं लिया।

■जुलाई 2024 में सेबी ने हमें कारण बताओ नोटिस भेजा था। जिसके जवाब में हमने लिखा था कि हमें यह अजीब लगा कि कैसे सेबी को एक रेगुलेटर होने के बावजूद फ्रॉड प्रैक्टिसेस को बचाने के लिए सेट-अप किया गया था।

■सेबी ने फ्रॉड प्रैक्टिसेस से जुड़ी पार्टियों की जांच करने में बहुत कम रुचि दिखाई। यह लोग पब्लिक कंपनियों के जरिए अरबों डॉलर के अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस में लगे हुए एक सीक्रेट ऑफशोर शेल एम्पायर को चलाते थे। इसके अलावा नकली निवेश एंटिटीज के एक नेटवर्क के जरिए अपने शेयरों को बढ़ाते थे।

■IPE प्लस फंड एक छोटा ऑफशोर मॉरीशस फंड है, जिसे अडाणी डायरेक्टर ने इंडिया इंफोलाइन के जरिए स्थापित किया है, जो वायरकार्ड स्कैंडल से जुड़ी एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है।

■गौतम अडाणी के भाई विनोद अडाणी ने इस स्ट्रक्चर का यूज इंडियन मार्केट्स में निवेश करने के लिए किया, जिसमें अडाणी ग्रुप को पावर इक्विपमेंट्स के ओवर इनवॉइसिंग से मिला फंड शामिल था।

■सेबी चीफ और उनके पति धवल बुच की अस्पष्ट ऑफशोर बरमूडा और मॉरीशस फंड में हिस्सेदारी थी। विनोद अडाणी ऑफशोर बरमूडा और मॉरीशस फंड का यूज भी स्ट्रक्चर की तरह करते थे।

■डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, माधबी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड-1 में अपना अकाउंड ओपन किया था।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में महिलाओं के लिए क्षमता संवर्धन कार्यक्रम में ए डिकेड ऑफ वूमेन एंपावरमेंट 2014 – 2024 पुस्तक भेंट की गई।

मान सिंह पटेल मामले में एसआईटी गठित

3 सदस्यीय टीम को भोपाल देहात आईजी अभय सिंह करेंगे लीड

विश्वास का तीर

सागर के गुम हुए मान सिंह पटेल मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (स्ङ्क्ष) का गठन कर दिया गया है। जिसमें भोपाल देहात के आईजी अभय सिंह को एसआईटी का चीफ नियुक्त किया है। सीहोर एसपी मयंक अवस्थी और पीएचक्यू में पदस्थ अनुराग सुजानिया को सदस्य बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को आईपीएस की एक नई एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था। एसआईटी आईजी रैंक के अफसर की अध्यक्षता में गठित करने के आदेश दिए गए थे।

जानिए, क्या है मामला

मान सिंह पटेल 2016 में लापता हो गए थे। जमीन विवाद मामले में उनके बेटे सीताराम ने उस समय के कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह राजपूत और उनके सहयोगियों पर पिता को गायब कराने का आरोप लगाया था। सीताराम ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने मान सिंह की गुमशुदगी दर्ज कर ली। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। इस एसआईटी की जांच को सुप्रीम कोर्ट ने महज दिखावा बताते हुए नई एसआईटी बनाने और इसमें दूसरे राज्यों के सीनियर आईपीएस अफसरों को शामिल कर जांच करने के निर्देश दिए हैं।

गोविंद सिंह पर लगाया था जमीन पर कब्जे का आरोप

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मान सिंह के बेटे सीताराम पटेल ने गोविंद सिंह राजपूत पर अपने पिता की गुमशुदगी और उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। इस मामले में ओबीसी महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सीताराम पटेल ने दावा किया था कि उनके पिता अगस्त 2016 में उस समय लापता हो गए, जब उन्होंने राजपूत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। यह शिकायत सागर जिले में उनकी पुश्तैनी जमीन पर राजपूत और उनके साथियों द्वारा अवैध कब्जा और निर्माण से संबंधित थी। सीताराम ने आगे आरोप लगाया कि उन्हें चुप कराने और संपत्ति पर कब्जा करने के लिए उनके पिता को गायब कराया गया था। स्थानीय प्रशासन और सीएम हेल्पलाइन को कई बार शिकायत करने के बावजूद मान सिंह का पता लगाने के लिए ठोस पुलिस कार्रवाई नहीं की गई।

मानसिंह पटेल
लापता ओबीसी नेता

संतोष श्रीवास्तव
इन्हें पुलिस ने उठाया

भोपाल मेट्रो के स्टील ब्रिज के रखे गर्डर

200 टन वजनी क्रेन की मदद से रखे 33.5 मीटर गर्डर; एक और ब्लॉक मिलेगा

विश्वास का तीर

भोपाल मेट्रो के स्टील ब्रिज के लिए रेलवे ट्रैक के ऊपर 33.5 मीटर लंबे गर्डर रख दिए हैं। अब एक और ब्लॉक मिलेगा। जिसमें 65 मीटर लंबे और 416 टन वजनी ओवन वेब गर्डर रखे जाएंगे। बता दें कि आरकेएमपी से डीआरएम ऑफिस के बीच रेलवे लाइन है। इसलिए 65 मीटर लंबा स्टील ब्रिज असेंबल किया गया। दोनों ओर कई महीने पहले ही पिलर खड़े हो चुके थे। रेलवे के ब्लॉक का इंतजार मेट्रो के अफसर कर रहे थे। यह ब्लॉक मिलते ही दोनों ओर गर्डर रख दिए गए। इस ब्रिज की चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर रहेगी। ताकि, नीचे ट्रेनें आसानी से गुजर सके।

मार्च में काम की शुरुआत हुई

इसी साल जनवरी-फरवरी में ब्रिज के पार्ट्स अलवर से भोपाल आ गए थे। जिन्हें मार्च में असेंबल करना शुरू किया गया। मार्च में काम की शुरुआत की गई। करीब छह महीने से रास्ता भी डायवर्ट किया गया है। दूसरी ओर, डीआरएम ऑफिस तिराहे की सड़क के ऊपर ब्रिज के पॉर्ट्स असेंबल किए जा चुके हैं। इसे भी पिलर के ऊपर रखा जाएगा। रेलवे क्रॉसिंग के बाद दूसरा ब्रिज डीआरएम ऑफिस चौराहे पर 48 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा ब्रिज बनेगा। यह भी 14 मीटर ऊंचा रहेगा। ब्रिज बनने के बाद नीचे गाड़ियां निकलेगी तो ऊपर मेट्रो गुजरेगी।

200 टन वजनी ट्रेन का उपयोग किया

मेट्रो कॉपोरेशन के अफसरों ने बताया कि भोपाल मेट्रो प्रॉयोरिटी कॉरिडोर के लिए हबीबगंज नाका रेलवे क्रॉसिंग पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सफलतापूर्वक पूरा किया। भारतीय रेलवे द्वारा दिए गए 2 घंटे के ब्लॉक के भीतर में 200 टन क्रेन का उपयोग करके रेलवे ट्रैक पर दो 33.5 मीटर एमजी गर्डर स्थापित किए हैं। अगला प्रमुख कार्य 65 मीटर और 416 टन के ओपन वेब गर्डर की स्थापना है।

भोपाल के टीटी नगर में युवक ने सुसाइड किया

फांसी लगाकर जान दी; रहवासी बोले- अफसर शेड तोड़ने की धमकी दे रहे थे

विश्वास का तीर

भोपाल की भदभदा बस्ती से टीटी नगर में शिफ्ट किए गए एक युवक ने गुरुवार रात फांसी लगा ली। परिजन और रहवासियों का आरोप है कि निगम और जिला प्रशासन के अफसर शेड तोड़ने की धमकी दे रहे थे। इसलिए युवक ने फांसी लगा ली। इधर, पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं। घटना के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, निगम में नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी समेत कई कांग्रेस मौके पर पहुंचे। रहवासियों ने बताया कि भदभदा बस्ती तोड़ने के बाद कुछ लोगों को टीटी नगर में शेड बनाकर दिए थे। इन्हें भी तोड़ने की निगम और प्रशासन के अफसर धमकी दे रहे थे। इससे चालक शादाब टेंशन में रहता था। गुरुवार देर शाम शादाब ने अपने ही घर में फांसी लगा ली।

परिजनों ने देखा तो हॉस्पिटल लेकर पहुंचे

शादाब का शव फांसी में लटका देख परिजन बेहोश हो गए। शोर सुनकर रहवासी मौके पर पहुंचे और शव उतारकर जेपी हॉस्पिटल पहुंचे। जहां डॉक्टर ने जांच की, लेकिन शादाब की मौत हो चुकी थी। टीटी नगर थाना प्रभारी मनोज पटवा ने बताया, रात 8 बजे जेपी हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। उसका नाम शादाब है। शनिवार को पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा। परिजनों से बात की है। सुसाइड नोट नहीं मिला है। जांच कर रहे हैं।

रोज 90 रेप केस हो रहे, सख्त कानून बनाए

कोलकाता रेप-मर्डर केस, ममता की मोदी को चिट्ठी

विश्वास का तीर

कोलकाता रेप-मर्डर केस में अब गुरुवार (22 अगस्त) को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। ममता ने पीएम को लिखा कि देश में रोज दुष्कर्म के 90 मामले सामने आते हैं। इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। इस बीच, सियालदह कोर्ट ने सीबीआई को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दे दी है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को अरेस्ट किया है। इसको लेकर देशभर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं।

ममता ने पीएम को लिखा- महिलाएं सुरक्षित महसूस करें

पश्चिम बंगाल की सीएम ने मोदी को लिखा- मौजूदा डेटा बताता है कि देश में रोज 90 रेप केस हो रहे हैं। ज्यादातर मामलों में रेप पीड़ित की हत्या हो जाती है। यह ट्रेंड भयावह है। यह समाज और देश के आत्मविश्वास और विवेक को झकझोर देता है। यह हमारा कर्तव्य है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार एक कड़ा कानून बनाए, जिसमें इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान हो। ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए। पीड़ित को जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि ट्रायल 15 दिन में पूरा कर लिया जाना चाहिए।

कोलकाता रेप-मर्डर मामले में 5 बड़े अपडेट्स

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि विशेष जांच टीम तब क्यों नहीं बनाई गई, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर पहली बार वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे। आरजी कर के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भ्रष्ट जांच को लेकर हाईकोर्ट में अपील की थी। इस पर आज सुनवाई हुई। कोलकाता रेप-मर्डर केस में तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस बात पर चिंता जताई कि डॉक्टर्स से अमानवीय तरीके से काम लिया जाता है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों को कभी-कभी 36 घंटे तक काम करना पड़ता है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य भवन का घेराव करने के लिए मार्च निकाला। इसी दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों ने कहा है कि वे हड़ताल जारी रखेंगे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान डॉक्टरों को काम पर लौटने को कहा है। दिल्ली-ढ्ढ्रूस्र के डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है।

फैक्ट-चेकर को जिहादी कहने वाले को हाईकोर्ट का आदेश

विश्वास का तीर

अल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को ट्विटर पर जिहादी कहने वाले एक शख्स को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वह अपने ट्विटर हैंडल पर माफीनामा पोस्ट करें। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि यह पोस्ट दो महीने तक ट्विटर अकाउंट पर रहना चाहिए। इस व्यक्ति ने 2020 में जुबैर को जिहादी कहा था। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने यह टिप्पणी 2020 के एक POCSO केस को खारिज करने के लिए लगाई गई याचिका की सुनवाई के दौरान दी। साथ ही कोर्ट ने मामले में जुबैर को क्लीन चिट दे दी है।

कोर्ट का आदेश- एक हफ्ते के अंदर माफीनामा पोस्ट करें

आदेश के मुताबिक जगदीश सिंह नाम के इस व्यक्ति को यह ट्वीट एक हफ्ते के अंदर करना होगा। इसमें लिखना होगा- मैं ऊपर किया कमेंट करने पर पछतावा महसूस कर रहा हूं। यह कमेंट मैंने किसी दुर्भावना या जुबैर को दुख पहुंचाने के इरादे से नहीं किया था। जगदीश सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि जगदीश अपने ट्विटर हैंडल पर माफीनामा पोस्ट करने को राजी है। इस पर कोर्ट ने जगदीश सिंह के वकील से कहा कि जगदीश अपने पिछले ट्वीट का हवाला देते हुए माफीनामा पोस्ट करें।

इसके साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जगदीश सिंह ट्रायल कोर्ट में कानूनी उपाय अपना सकते हैं, जहां मामला अभी पेंडिंग है।

क्या था पूरा मामला

2020 में जगदीश सिंह ने मोहम्मद जुबैर को लेकर ट्वीट किया था। इसमें उसने कहा था- वन्स ए जिहादी इज ऑलवेज जिहादी (जिहादी हमेशा जिहादी ही रहता है)। इसे लेकर जुबैर ने जगदीश सिंह के डिस्प्ले पिक्चर को रिट्वीट करते हुए उसे ट्रोल कहा था। डिस्प्ले पिक्चर में जगदीश सिंह की पोती की तस्वीर थी, जिसे जुबैर ने ब्लर कर दिया था। तस्वीर के साथ जुबैर ने ट्वीट किया था- हेलो जगदीश सिंह, क्या तुम्हारी प्यारी पोती ये जानती है कि तुम सोशल मीडिया पर लोगों को ट्रोल करने की पार्ट टाइम नौकरी करते हो? मेरा सुझाव है कि तुम प्रोफाइल पिक बदल लो। जुबैर के ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने POCSO एक्ट के कुछ प्रावधानों, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट और इंडियन पीनल कोड के तहत स्नढ्ढक्र दर्ज की। जुबैर पर आरोप लगाया गया कि उसने ट्विटर पर नाबालिग लड़की को डराया और परेशान किया है। बाद में पुलिस ने हाईकोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल कर कहा कि उसने चार्जशीट में जुबैर का नाम नहीं लिखा है क्योंकि उसके खिलाफ किसी अपराध का सबूत नहीं मिला है। हालांकि हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई कि जुबैर के खिलाफ हेट-स्पीच देने वाले जगदीश सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली पुलिस ने जगदीश सिंह की जांच की और कहा कि उसके पास से कोई आपराधिक चीज नहीं मिली है। पुलिस ने एक रिपोर्ट फाइल की और कहा कि सिंह के ट्वीट से लोगों के बीच डर या परेशानी का माहौल नहीं बना, इसलिए उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया गया।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक एवं सपांदक आयुष राजपूत द्वारा कविता आर्फसेट प्रिंटर्स, एमपी नगर जोन -1 भोपाल (म. प्र.) से मुद्रित एवं 1209 पुष्पा नगर चांदबड़, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- आपयुष राजपूत, मो.7247257823, 7999252366 (प्रति शुक्रवार को प्रकाशित) समाचारों से संपादक का सहमत होना जरूरी नहीं। (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा।) RNI.NO MPHIN/2022/83636